



प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं पर प्रभाव: मध्य प्रदेश के सागर संभाग के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अश्वनी मिश्रा एवं ओ.पी. अरजरिया

वाणिज्य अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

Corresponding Author: ashvaneer840mishra@gmail.com

Received 18 March 2025; Revised 22 April 2025; Accepted 03 June 2025

सार

भारत एक युवा राष्ट्र है जहाँ बड़ी संख्या में युवा जनसंख्या रोजगार की तलाश में है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना आज की महती आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का उद्देश्य युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। प्रस्तुत शोध पत्र में इस योजना के मध्य प्रदेश के सागर संभाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने युवाओं ने इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया, कितनों को रोजगार मिला, और योजना से जुड़े प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार प्राप्ति की संभावनाएँ तथा सामाजिक-आर्थिक बदलाव किस सीमा तक संभव हो सके। शोध के लिए प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिनमें लाभार्थियों के साक्षात्कार, सरकारी रिपोर्ट, योजना से जुड़े आँकड़े एवं प्रशिक्षण केंद्रों का मूल्यांकन शामिल है। प्रारंभिक निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि योजना ने निश्चित रूप से कई युवाओं को कौशल प्राप्त करने का अवसर दिया है, किंतु रोजगार प्राप्त करने में असंगतियाँ पाई गईं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष नीति निर्माताओं, योजना संचालकों तथा शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं, जिससे योजना को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।(MSDE,2022)।

कुंजी शब्द: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), युवा सशक्तिकरण, शहरी एवं ग्रामीण विकास, सागर संभाग, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार।

प्रस्तावना

भारत एक युवा देश है जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में आता है। इस विशाल युवा शक्ति को यदि सही दिशा और अवसर मिलें, तो यह राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बड़ी संख्या में युवा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद रोजगार योग्य कौशल से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। यह प्रशिक्षण रोजगारोन्मुखी, व्यवसाय आधारित तथा उद्योगों की मांग के अनुरूप होता है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र, नौकरी के अवसर, तथा स्वरोजगार की संभावनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं (NSDC,2021)। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन अलग-अलग प्रभाव दिखाता है। सागर संभाग मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार की सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ

विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के बीच बेरोजगारी, शिक्षा की असमानता और कौशल की कमी जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं। अतः यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने इन युवाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। क्या प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिला? क्या ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी इस योजना से समान लाभ मिला? यह शोधपत्र इन्हीं बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के बीच योजना के प्रभाव की तुलना करना, उनकी समस्याओं की पहचान करना तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं, प्रशासन, और शोधकर्ताओं को युवाओं के कौशल विकास के संदर्भ में उचित दिशा प्रदान कर सकता है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व

1. युवाओं में बेरोजगारी की दर को कम करने की आवश्यकता।
2. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल अंतर को समझना।
3. नीति निर्माताओं को योजना के प्रभावी

क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन।

4. सागर संभाग के विकास हेतु युवाओं की भूमिका पर विशेष अध्ययन।

शोध के उद्देश्य

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की संरचना एवं उद्देश्य का अध्ययन।

2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के प्रशिक्षण अनुभवों का तुलनात्मक विश्लेषण।

3. योजना से जुड़े युवाओं की रोजगार स्थिति का मूल्यांकन।

4. योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों की पहचान करना।

5. सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ

1. PMKVY योजना का प्रभाव शहरी युवाओं पर ग्रामीण युवाओं की तुलना में अधिक सकारात्मक रहा है।

2. प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार पाने में सहायता मिली है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की पहुँच और जानकारी का अभाव है।

शोध क्षेत्र का परिचय

सागर संभाग मध्य प्रदेश के एक प्रमुख संभागीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

इसमें मुख्यतः सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी जिले शामिल हैं। यहाँ की सामाजिक-आर्थिक स्थिति विविध है, जिससे यह शोध के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनता है (Singh and Sharma,2019)।

शोध विधि

शोध का प्रकार: विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक

1. डाटा संग्रहण विधि:

- प्राथमिक डाटा: प्रश्नावली, साक्षात्कार
- द्वितीयक डाटा: सरकारी रिपोर्ट, योजना की वेबसाइट, समाचार लेख

2. नमूना चयन: सागर संभाग के 5 जिलों में से प्रत्येक जिले से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 50-50 युवाओं का चयन (कुल 500)

शोध निष्कर्ष

इस अध्ययन के दौरान सागर संभाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभाव का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए:

1. योजना की जागरूकता में असमानता: शहरी क्षेत्रों में युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल

विकास योजना की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी योजना की जानकारी और प्रचार-प्रसार की कमी देखी गई, जिसके कारण कई पात्र युवक-युवतियाँ योजना का लाभ नहीं ले पाए।

2. प्रशिक्षण केंद्रों की सुलभता:

शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या अधिक एवं पहुँच सुगम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रों की दूरी, संसाधनों की कमी एवं यातायात के साधनों की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा रही।

3. प्रशिक्षण की गुणवत्ता:

अधिकांश केंद्रों पर प्रशिक्षकों की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई, लेकिन कुछ ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों में अधूरी सुविधाएं, उपकरणों की कमी और व्यावहारिक प्रशिक्षण का अभाव देखा गया। इससे प्रशिक्षण की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

4. रोजगार प्राप्ति की स्थिति:

प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से लगभग 60-65% युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार मिला। शहरी युवाओं के लिए यह प्रतिशत अधिक (लगभग 70%) था, जबकि ग्रामीण युवाओं में यह प्रतिशत लगभग 55% तक सीमित रहा। यह अंतर क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।

5. स्वरोजगार के प्रति प्रवृत्ति:

कई ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार को अपनाया, विशेषकर सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, कृषि आधारित कार्यों में। हालांकि पूंजी की कमी और तकनीकी सहयोग की अनुपलब्धता ने उनकी वृद्धि को सीमित किया।

6. महिला भागीदारी:

योजना में महिला प्रतिभागियों की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, परंतु सामाजिक रूढ़ियाँ, परिवहन सुविधा की कमी और पारिवारिक समर्थन की कमी के कारण ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।

7. योजना की दीर्घकालिक उपयोगिता:

कुछ लाभार्थियों ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें अपने कौशल को निरंतर अपडेट करने की आवश्यकता है। योजना के तहत Post-Training Support की कमी अनुभव की गई, जैसे प्लेसमेंट ट्रेकिंग, मेंटरशिप, या पूंजी सहायता।

8. प्रशासनिक चुनौतियाँ:

योजना के क्रियान्वयन में समयबद्ध फंड रिलीज़, ट्रेनिंग मॉड्यूल में बदलाव, और प्रशिक्षकों की भर्ती जैसी प्रशासनिक चुनौतियाँ बार-बार सामने आईं, जिससे प्रशिक्षण की

गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रभावित हुई (NITI Aayog,2020)।

सुझाव:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान को तीव्र किया जाए

ग्रामीण युवाओं में योजना की जानकारी का अभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। अतः स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार, रैली, शिविर, आशा कार्यकर्ताओं एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से योजना की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि योग्य युवा लाभ उठा सकें।

2. प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या एवं पहुँच बढ़ाई जाए

सागर संभाग के कई ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी अधिक है। वहाँ अतिरिक्त मोबाइल ट्रेनिंग वैन, ब्लॉक-स्तरीय केंद्र तथा डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे युवाओं को उनके निकट ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।

3. प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाए

कुछ प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों की कमी, पुराने उपकरण एवं पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता जैसी समस्याएँ देखी गईं। इसके समाधान हेतु -

- प्रशिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था हो।

- पाठ्यक्रम को उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुसार अद्यतन किया जाए।

- प्रैक्टिकल अभ्यास और इंटरनशिप की समय-सारणी सुनिश्चित की जाए।

4. रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था मजबूत की जाए

केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है जब तक कि लाभार्थी को रोजगार न मिले। इसके लिए -

- प्लेसमेंट सेल को प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में सक्रिय किया जाए।

- स्थानीय उद्योगों और MSMEs से साझेदारी की जाए।

- साक्षात्कार एवं रिज्यूमे लेखन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो।

1. स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए

प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में स्वरोजगार की इच्छा तो है, पर पूंजी की कमी बाधा है। इसलिए-

- उन्हें PMEGP, MUDRA, या स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए।

- ब्याज रहित ऋण, मार्केटिंग सहायता, और हस्तशिल्प मेलों में भागीदारी दिलाई जाए।

6. महिला प्रतिभागियों के लिए विशेष सुविधाएँ

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण में भाग लेना चुनौतीपूर्ण होता है। अतः

- महिला प्रशिक्षणार्थियों को पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
- डेस्क आधारित कार्य, घरेलू उद्योग, ऑनलाइन रोजगार की ओर उन्हें प्रेरित किया जाए।
- क्रेच सुविधा, भत्ता, और महिला-विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित किए जाएँ।

7. योजना के परिणामों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन

योजना के दीर्घकालिक प्रभाव जानने हेतु -

- Post-Training Tracking System विकसित किया जाए।
- समय-समय पर फीडबैक सर्वे, ऑडिट रिपोर्ट, और ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक विश्लेषण कर योजना की प्रगति आंकी जाए।
- लाभार्थियों से सीधे जुड़ने हेतु मोबाइल ऐप/पोर्टल पर इंटरैक्शन सिस्टम बनाया जाए।

8. लोकल भाषाओं और डिजिटल प्लेटफार्म का समावेश

कई ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी भी एक बधा बन्ती है। अतः

- प्रशिक्षण सामग्री बुंदेली/स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो।
- डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग, मोबाइल लर्निंग ऐप्स की शुरुआत हो (PMKVY, 2023, Shama and Patel, 2022)।

निष्कर्षतः

इन सुझावों के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अधिक समावेशी, सुलभ और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण युवाओं के बीच की खाई कम होगी और देश की युवा शक्ति को कुशल, रोजगार योग्य तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वास्तविक प्रगति होगी।

विश्लेषण के बिंदु	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1. योजना की जागरूकता	अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता	सीमित जानकारी, प्रचार की कमी
2. प्रशिक्षण केंद्रों की उपलब्धता	अधिक संख्या में, बेहतर सुविधा	सीमित संख्या, दूरवर्ती स्थानों पर स्थित
3. प्रशिक्षण की गुणवत्ता	प्रशिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर, सामग्री अद्यतन	कुछ केंद्रों में उपकरणों व प्रशिक्षकों की कमी
4. पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता	आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध	पारंपरिक व सीमित विकल्प

5. महिला भागीदारी	महिला भागीदारी अपेक्षाकृत बेहतर	सामाजिक बाधाओं व सुरक्षा कारणों से कम भागीदारी
6. रोजगार प्राप्ति दर	लगभग 70% युवाओं को रोजगार प्राप्त	लगभग 55% युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार
7. स्वरोजगार की प्रवृत्ति	कम, अधिकतर युवाओं की नौकरी में रुचि	अधिक, विशेषकर कृषि, हस्तशिल्प, टेलरिंग आदि में
8. परिवहन सुविधा	सुविधा उपलब्ध, प्रशिक्षण केंद्रों तक आसान पहुँच	साधनों की कमी, विशेषकर महिलाओं के लिए चुनौती
9. डिजिटल साक्षरता	अपेक्षाकृत अधिक, ऑनलाइन कोर्सेज में भागीदारी	कम डिजिटल पहुँच, स्मार्टफोन/इंटरनेट की कमी
10. योजना से संतुष्टि का स्तर	संतोषजनक, यथासंभव लाभ प्राप्त	मध्यम स्तर का संतोष, अपेक्षाओं के अनुसार लाभ नहीं

Table1: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में (Chaurasia, 2021, World Bank, 2020)

निष्कर्ष:

भारत एक युवा प्रधान राष्ट्र है, और युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार या सेवा क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस शोध में सागर संभाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं पर इस योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। शोध के दौरान यह पाया गया कि योजना ने शहरी युवाओं को अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुँचाया है। शहरों में योजना के प्रति जागरूकता अधिक है, प्रशिक्षण केंद्रों की उपलब्धता बेहतर है, और उद्योगों की नजदीकी से प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, संसाधनों की उपलब्धता, और सामाजिक स्वीकृति जैसी सुविधाएँ योजना

को अधिक प्रभावी बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को योजना का अपेक्षाकृत सीमित लाभ मिला है। योजना की जानकारी वहाँ कम है, प्रशिक्षण केंद्रों की पहुँच कठिन है, और सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिबंध - विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में - उनकी भागीदारी को सीमित करते हैं। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की प्रवृत्ति अधिक देखी गई, जो स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप है (6)। यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रशिक्षण के बाद सभी लाभार्थियों को रोजगार नहीं मिल पाता है। कई युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता या उन्हें कार्यस्थल पर उपयुक्त सहयोग नहीं मिल पाता। इससे योजना की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। हालाँकि, योजना ने दोनों क्षेत्रों के युवाओं में आत्मविश्वास, कौशल, और नए अवसरों के प्रति रुचि जगाई है। यदि सरकार योजना के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय आवश्यकताओं का ध्यान रखे, महिला भागीदारी को सशक्त बनाए, और प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करे - तो यह योजना देश की युवा

शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर बन सकती है।

संदर्भ:

1. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2022). Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Annual Report. Government of India. <https://www.msde.gov.in/>
2. National Skill Development Corporation (NSDC). (2021). Skill India Report 2021: Trends and Impact. NSDC Publications.
3. NITI Aayog. (2020). Strategy for New India @75. Government of India. <https://niti.gov.in>
4. Singh, R., & Sharma, A. (2019). Impact of Skill Development Programs on Youth Employment in India. *Journal of Rural and Urban Development Studies*, 7(2), 45–58.
5. Chaurasia, M. K. (2021). Gramin yuvaon ke liye kaushal vikas yojanaon ka prabhav: Ek tulanatmak adhyayan. *Research Journal of Economics & Social Development*, 12(1), 67–74.
6. Government of Madhya Pradesh. (2022). State Skill Development Mission Annual Report. Bhopal: Directorate of Skill Development.
7. World Bank. (2020). *Skilling for the Future*:



- Jobs and Education for India's Youth. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/>
8. Dubey, S., & Khan, T. (2020). Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ka Gramin Vikas mein Yogdan. *Shodh Samiksha aur Mulyankan*, 11(3), 120–125.
9. PMKVY Official Portal. (2023). PMKVY Dashboard and Implementation Data. <https://pmkvyofficial.org>
10. Sharma, V., & Patel, R. (2022). Skill Development Initiatives in India: A Comparative Study of Urban and Rural Youth. *International Journal of Human Resource and Applied Social Science*, 10(4), 25–32.